

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. ~~आयुक्त,~~
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निबंधक,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, उत्तराखण्ड।

2. नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 12 जून, 2008

विषय: खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के आपूर्ति, विपणन एवं विधिक माप विज्ञान तथा राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण/जिला फोरमों के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2008-09 हेतु स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति से संबंधित कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 588/XXX(2)/2008, दिनांक 29 मई, 2008 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में आपूर्ति, विपणन एवं विधिक माप विज्ञान तथा जिला फोरमों में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति को उसी रूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे जिसमें एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3. वार्षिक स्थानान्तरण/परिवर्तन/निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की संस्तुति करेगी और उस संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेंगे। स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेंगे और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

समूह "ख" के जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों के लिये उनके द्वारा किये जाने वाले संवेदनशील कार्य को देखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती की अवधि 03 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष होगी तथा इनका स्थानान्तरण शासन द्वारा ही किया जायेगा।



4. वार्षिक स्थानान्तरण सुगत क्षेत्रों में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक सीमित रखे जायेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे।
 5. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तीनों शाखाओं (पूर्ति, विपणन तथा विधिक माप) के समूह "ग" में कार्यरत वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों को प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरणों को छोड़कर समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03 से 05 वर्ष होगी किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।
 6. विपणन शाखा के अन्तर्गत वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों को स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा तथा निरीक्षकों एवं लिपिक संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा किये जायेंगे। अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा किये जायेंगे।
 7. पूर्ति शाखा के अन्तर्गत वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों/पूर्ति निरीक्षकों/लिपिक संवर्ग का स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त किये जायेंगे।
 8. जिला पूर्ति कार्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को सृष्ट करने एवं कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिये समूह "ग" के पदों पर कार्यरत पूर्ति लिपिकों/ज्येष्ठ लेखा लिपिकों/प्रधान लिपिकों/आशुलिपिकों का स्थानान्तरण मण्डल के अन्तर्गत अधिकतम 03 से 05 वर्ष की सेवा करने के बाद एक जनपद से दूसरे जनपद में सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, खाद्य) द्वारा स्थानान्तरण किया जायेगा, परन्तु पूर्व तैनाती में पुनः तीन वर्ष से पहले स्थानान्तरण न किये जायें। लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को जनपद में एक काउन्टर पर दो वर्ष की अवधि पूरी करने पर अवश्य स्थानान्तरित कर दिया जाये। सभी शाखाओं के समूह "ग" के कार्मिकों के मामले में कार्मिक विभाग द्वारा तैनाती की अवधि के अलावा लगाये गये अन्य प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
 9. किसी भी जनपद में स्वीकृत पदों से अधिक कार्मिक तैनात नहीं किये जायेंगे तथा जिन जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कर्मचारी तैनात हैं उन्हें जनपद में तैनाती की अधिक अवधि को आधार मानते हुए अन्य जनपदों में जहाँ स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की तैनाती की संख्या कम है प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जायेगा तथा इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि पर्वतीय जनपदों एवं दुर्गम स्थानों पर पद रिक्त न रहे।
- राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
10. विधिक माप विज्ञान (बाट माप) शाखा के समूह 'ग' के वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक का स्थानान्तरण नियंत्रक द्वारा तथा वरिष्ठ सहायकों/कनिष्ठ सहायकों तथा समूह 'घ' के प्रयोगशाला परिचर एवं संदेश वाहक तथा चौकीदार का स्थानान्तरण सहायक नियंत्रक द्वारा तथा संभाग से बाहर नियंत्रक स्तर से तथा संभाग के अन्दर 03 वर्ष के बाद एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला पर सहायक नियंत्रक स्तर से चयन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
 11. स्थानान्तरण नीति के अतिरिक्त गंभीर रूप से बीमार कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार शासन स्तर से ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
 12. विगत 05 वर्षों से पूर्ति निरीक्षकों, विपणन निरीक्षकों के पद पर प्रोन्नत कार्मिक जो उसी जनपद अथवा मण्डल में कार्यरत हैं उन्हें दूसरे जनपदों/मण्डलों में स्थानान्तरित किया जायेगा, यह स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य के स्तर से किये जायेंगे और शासन स्तर से कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक: 29 मई, 2008 के अनुसार 15 जून, 2008 के बाद यदि किसी विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो एवं अपरिहार्य हो तो उस दशा में समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे, समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने किये जायेंगे तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे।

13. जनहित एवं प्रशासनिक हित में शासन स्तर से किसी भी कर्म का स्थानान्तरण कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है तो उसे इस कृत्य/आचरण के लिए सरकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों की परिधि में आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त स्थानान्तरण यथा संभव 15 जून, 2008 तक पूर्ण कर लिये जाये।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा० सुनील सिंह)
सचिव।

संख्या: 605(1)/XIX-I/08-61/2006, तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2 अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
- 3 सहायक आयुक्त, मुख्यालय (खाद्य) गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6 निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य विभाग।
- 7 निजी सचिव, अपर सचिव, खाद्य विभाग।
- 8 निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड।
- 9 समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तराखण्ड।
- 10 समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
- 11 सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।
- 12 समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 13 एन०आई०सी०, सचिवालय, परिसर, देहरादून।
- 14 खाद्य अनुभाग - 1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
- 15 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)

अपर सचिव।